भारत सरकार संचार मंत्रालय दूरसंचार विभाग लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.2865 उत्तर देने की तारीख 20 दिसम्बर, 2023

4जी सेचुरेशन टावर

2865. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील:

श्री बी.वाई. राघवेन्द्रः

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) क्या सरकार को दिसंबर, 2023 के अंत तक महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्रमशः सतारा और शिवमोग्गा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में यूएसओएफ निधि द्वारा 4जी सैचुरेशन परियोजना के तहत स्वीकृत बीएसएनएल मोबाइल टावरों के निर्माण के पूरा होने के विषय में जानकारी है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत पांच वर्षों के दौरान बनाए गए 4जी सैचुरेशन टावरों की संख्या कितनी है और उक्त परियोजना के लिए कितनी धनराशि दी गई/व्यय की गई है;
- (ग) क्या सरकार को जानकारी है कि पूरे देश में एक ही ठेकेदार को नियुक्त करने और दिसंबर, 2023 से पहले कार्य पूरा करने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की नियुक्ति न करने के कारण कार्य प्रगति में बाधा आ रही है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परियोजना को गति देने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है; और
- (ङ) क्या सरकार को पूर्ण किए गए मोबाइल टावरों को मोबाइल नेटवर्क का कार्यकरण शुरू करने के लिए रेडियो उपकरण, सौर पैनल, डीजल जेनरेटर और अन्य संबंधित उपकरण उपलब्ध न कराने के बारे में जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर संचार राज्य मंत्री (श्री देवुसिंह चौहान)

(क) से (ङ) पिछले 10 वर्षों में देश में दूरसंचार कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। बीटीएस (बेस ट्रांसीवर स्टेशन) की कुल संख्या मार्च-2014 में 6.49 लाख से बढ़कर मार्च-2023 में 25.42 लाख हो गई है। कुल मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या मार्च 2014 में 90.45 करोड़ से बढ़कर अगस्त 2023 में 114.84 करोड़ हो गए हैं। इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या मार्च-2014 में 25.15 करोड़ से बढ़कर मार्च-2023 में 88.12 करोड़ हो गए हैं।

सितंबर 2023 तक देश के 6,44,131 गांवों में से (भारत के महापंजीयक के अनुसार गांव का डेटा) लगभग 6,16,300 गांव 95.7% की मोबाइल कनेक्टिविटी कवरेज से कवर हैं।

देश के सेवा से वंचित गांवों में दूरसंचार कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कई स्कीमें शुरू की है। सरकार ने 41,331 करोड़ रुपये से अधिक के परिव्यय से 54,000 से अधिक गांवों में कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए देश के सेवा से वंचित क्षेत्रों में 41,160 टावरों लगाने की योजना बनाई है।

दिनांक 31.10.2023 के स्थिति के अनुसार सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) के तहत विभिन्न स्कीमों से देश में कुल 6,394 मोबाइल टावर पहले ही चालू किए जा चुके हैं जो राष्ट्रीय राजमार्ग स्थलों सहित 7,535 गांवों को कवर करते हैं।

इन टावरों के कार्यान्वयन के लिए दूरसंचार विभाग राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों के साथ समन्वय कर रहा है। उपकरणों की आपूर्ति और अन्य कार्यों में तेजी लाने के लिए सभी हितधारकों के साथ नियमित समन्वय बैठकें की जा रही हैं।
